

भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वॉटर ट्रीटी को रद्द किया

भारत के विदेश मंत्रालय ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्युरिटी की बैठक में हुए इस अहम् फैसले की जानकारी दी

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 23 अप्रैल। भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वॉटर ट्रीटी (आई.डब्ल्यू.टी.) को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियाँ खत्म होने तक यह रोक जारी रहेगी। इसी के साथ कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं, जिनमें वाघा-अटारी चैक पोस्ट बंद करने। पाकिस्तानियों का वीसा रद्द करना आदि शामिल है।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसे कथित रूप से पाकिस्तान के आतंकी गुटों ने अंजाम दिया है, के बाद से भारत के सामरिक एवं राजनैतिक हलकों में फिर से यह बात उठने लगी कि भारत को इंडस वॉटर ट्रीटी को निलम्बित कर देना चाहिए। यह अपील कथित रूप से पूर्व विदेश सचिव कंवल सिम्बल ने की है, जो इस समय जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने कहा, इस तरह से पाकिस्तान को कराचा जवाब दिया जा सकता है, जिसके आतंकी हमले में भारत की ही जमीन पर 28 लोग मारे गए हैं।

वरिष्ठ वकील एवं राज्यसभा सांसद कपिल सिम्बल ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इसे एक

■ पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत के सामरिक एवं राजनैतिक हलकों में इंडस वॉटर ट्रीटी रद्द करने की मांग जोर-शोर से उठी थी।

■ इस संधि के तहत पूर्वी भाग की रावी व्यास और सतलुज नदियों पर भारत का नियंत्रण है, तो सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान का नियंत्रण है।

■ पाकिस्तान का अस्तित्व एक तरह से इस संधि पर निर्भर है। पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था इसी के सहारे जीवित है।

■ गौरतलब है कि 1960 में विश्व बैंक ने भारत व पाकिस्तान के बीच यह संधि करवाई थी और यह दो परस्पर विरोधी पड़ोसी देशों के बीच सहयोग का दुर्लभ उदाहरण मानी जाती रही है। तीन युद्धों व दशकों से पाकिस्तान द्वारा भारत में किए जा रहे आतंकी हमलों के बावजूद यह संधि कायम रही।

सुनियोजित साजिश रच कर किया गया क्रूर कृत्य बताया उन्होंने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाने और विश्वस्त उत्तरदायित्व तय करने के लिए जोर देने की बात कही।

सिम्बल ने कहा कि पाकिस्तान को औपचारिक रूप से आतंकवादी राष्ट्र

घोषित कर देना चाहिए और जिन्होंने ये हत्याएं की हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आई.डब्ल्यू.टी. पर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे और विश्व बैंक ने यह संधि करवाई थी। आई.डब्ल्यू.टी. को दो शत्रु पड़ोसी राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग

की नायाब मिसाल माना जाता है। सवाल यह नहीं है कि संधि को निलम्बित किया जाना चाहिए, बल्कि यह है कि क्या ऐसा करना सार्थक और रणनीतिक रूप से बुद्धिमानी भरा कदम होगा।

तीन बड़े युद्धों और कई दशकों की शत्रुता के बाद भी यह संधि कायम रही, क्योंकि दोनों देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी अहम भूमिका है। इसके तहत रावी, व्यास और सतलुज जैसे पूर्वी नदियों पर भारत का नियंत्रण है और सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, भारत को इन नदियों के पानी के सीमित उपयोग की अनुमति है।

कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, अगर भारत ने एक तरफा निर्णय कर इस संधि को खत्म कर दिया तो नियमों का पालन करने वाले कानून परस्त देश के रूप में भारत की छवि को भारी धक्का लगेगा और क्षेत्रीय जल विवाद में गलत मिसाल बनेगी।

कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो आई.डब्ल्यू.टी. को निलम्बित करने से भारत को कोई तत्कालिक लाभ नहीं मिलेगा। पानी रोकने या उसका प्रवाह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जैसलमेर के 32 लोग पहलगाम में फंसे

जैसलमेर, 23 अप्रैल (नि.सं.)। जैसलमेर से कश्मीर वैली गए बड़ी संख्या में सैलानी अपने परिवार के साथ पहलगाम के होटल में फंसे हुए हैं। पहलगाम प्रशासन द्वारा सभी होटल संचालकों को फिलहाल अगले आदेशों तक किसी भी सैलानी को होटल से चेकआउट करने पर अंतरिम रोक लगाई है, इसके कारण ये सैलानी होटल में ही

■ प्रशासन ने अगले आदेशों तक सभी होटल संचालकों को किसी भी सैलानी को "चेक आउट" नहीं करने देने के लिये कहा है।

रकने को मजबूर है।

जैसलमेर में व्यापार करने वाले विपुल भाटिया पुत्र विमल भाटिया के परिवार के 4 लोगों सहित, उनकी मित्र मंडली के करीब 32 लोग अपने बच्चों सहित पहलगाम के एक होटल में दहशत के साए में हैं। आतंकी हमले के दौरान भी वे पहलगाम में ही थे। अब हमले के बाद ये किसी को होटल से चेकआउट नहीं मिल रहा है। अर्णव हतियारा भाटिया के परिवार भी 32 लोगों में शामिल है।

भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर से भारी समर्थन मिला

कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्युरिटी की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कठोर फैसले लिए प्र.मंत्री मोदी ने

■ भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क के तहत प्राप्त वीजा रियायत रद्द कर दी।

■ भारत में मौजूद सभी पाक नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया।

■ अटारी वाघा चैक पोस्ट बंद। वैध तरीके से आए लोग एक मई तक लौट सकते हैं।

■ पाक उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौ सेना व वायु सेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया। एक सप्ताह में देश छोड़ने के आदेश दिए।

■ पाक उच्चायोग में अब 50 की बजाय 30 लोग ही रह सकेंगे।

—अंजन राय—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। कश्मीर की पहलगाम घाटी में पर्यटकों पर हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। लेकिन भारत के हाथ कुछ हद तक बंधे हुए हैं, क्योंकि भारत पहले ही कह चुका है कि "यह युद्ध का युग नहीं है। यह कूटनीति और संवाद का युग है।"

तथापि, अगर भारत कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो आज की तारीख में वैश्विक कूटनीतिक माहौल उसके साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से भारत का समर्थन किया, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यहां तक कि, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत के पक्ष में रुख अपनाया। इजरायल ने भी भारत के प्रति जोरदार समर्थन व्यक्त किया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी भारत का समर्थन किया है और पूरी तरह से उसके साथ खड़े हुए हैं।

इस समय पाकिस्तान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई, अब कहीं अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन वाले वातावरण में

की जा सकती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता में बैठे लोग यह सोच कर आश्वस्त थे कि कश्मीर और घाटी अब धीरे-धीरे एक सामान्य स्थान बन रही है, जहाँ लोग रोजमर्रा की तरह घूम सकते हैं।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद, कश्मीर तेजी से स्थिरता की ओर लौट रहा था और आम जनजीवन ऐसा बनता जा रहा था, जिसे दुनिया के अन्य

हिस्सों में "सामान्य" कहा जाता है।

पर्यटन, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तेजी से बढ़ रहा था और इस वर्ष पर्यटकों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना थी। इसका अर्थ था कि आम कश्मीरियों की समृद्धि बढ़ रही थी, आय बढ़ रही थी और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ भी गति पकड़ रही थीं। इस आतंकी हमले ने, सामान्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आतंकवाद के खिलाफ हम सब सरकार के साथ हैं'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केन्द्रीय सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह करते हुए कहा

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 23 अप्रैल। पहलगाम आतंकी हमले को भारत की एकता और अखंडता पर सीधा हमला बताते हुये, कांग्रेस ने बुधवार को केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि इस घटना को लेकर एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाये। कांग्रेस ने जोर देते हुये कहा कि यह सामूहिक संकल्प का समय है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह समय एकापतपूर्ण राजनीति का नहीं है। यह क्षण उन लोगों के लिये न्याय सुनिश्चित करने के सामूहिक संकल्प का क्षण है। यह क्षण इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले अपराधियों को कटघरे में खड़ा करने का क्षण है ताकि इस हमले में मरने वालों तथा उनके दुखी परिवारों के प्रति न्याय हो सके।

कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह भारत

■ सूत्रों से पता चला है कि केन्द्र सरकार गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुला सकती है, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा, "पूरा राष्ट्र स्तब्ध है। एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हमें इसका माफ़ कूल जवाब देना होगा। हम सब एक हैं और (एकजुट होकर) संघर्ष करेंगे। बिना कुछ किये, बिना समुचित प्रबंध तथा बिना ऊंगली उठाये, कोई दावे नहीं किये जाने चाहिये।"

उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाने

का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि पूरी जानकारी प्राप्त होने तथा आवश्यक कार्यवाही करने से पहले सभी राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श किया जाये, ताकि सर्वसम्मत भावना के साथ आतंकवाद की चुनौती का सामना किया जा सके। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिये तथा सलाह-मशविरा करना चाहिये। यह राजनीति नहीं है तथा नहीं चाहते कि इस स्थिति में राजनीति हो।

उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2000 के चित्तौंसिंहपुरा के नरसंहार के बाद, पहलगाम हमला आतंकियों की निरलज्ज, नृशंस एवं घृणित कोशिशों में से एक है। कांग्रेस प्रमुख ने इस हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के पर्यटन उद्योग को लगने वाले संभावित धक्के को लेकर भी चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से प्रभावित होने वाले लोगों की मदद का अनुरोध किया। खड़गे ने कहा, "मामों की ऋतुशुरु (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पूरा सहयोग देगा-उपराष्ट्रपति वैंस

नयी दिल्ली, 23 अप्रैल। भारत की यात्रा पर आये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वैंस ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से टेलीफोन पर बात की और पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले की भर्त्सना की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की ओर से सभी प्रकार के सहयोग की पेशकश की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां एक्स पर आधिकारिक हेंडल पर अपने संदेश में लिखा, उपराष्ट्रपति जे डी वैंस ने

■ वैंस से यह पेशकश प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत में की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की और जम्मू कश्मीर में हुए नृशंस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने जान-माल के नुकसान पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और दोहराया कि अमेरिका इस कठिन घड़ी में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

'कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है', क्या आतंकी हमले का पूर्व संकेत था, पाक जनरल का यह बयान

पाक जनरल के इस बयान के कुछ ही दिन बाद, पहलगाम में भीषण आतंकी हमला हुआ है

—श्रीनंद झा—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। सूत्रों ने कहा कि पहलगाम हत्याओं के जवाब में, सरकार कूटनीतिक तथा सैन्य- दोनों ही विकल्पों पर विचार कर रही है।

इस समाचार को लिखते समय, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में "कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्युरिटी अफेयर्स" की मीटिंग चल रही है, जिसमें सभी संभव विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर, प्रधानमंत्री आज स्वदेश आ गये तथा आने के तुरंत बाद, विभिन्न मीटिंगों में कश्मीर के सुरक्षा-परिदृश्य पर पुनर्विचार किया। गृह मंत्री अमित शाह स्थिति के पुनर्विचार के लिये मंगलवार को श्रीनगर चले गये थे। जहाँ संपावित सैन्य विकल्प पर चल रहे विचार-विमर्श के बारे में अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है, वहीं उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों

■ गले की नस (जुगलर वेन) शरीर का वह अंग है, जिसे काटने से तुरंत मौत हो जाती है, तो क्या पाक जनरल यह कहना चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है?

■ विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस भारत यात्रा पर हैं, ऐसे में आतंकी हमले को अंजाम देकर दुनिया भर में भारत की "मजबूत राष्ट्र" की छवि पर आघात पहुँचाने की कोशिश की जा रही है।

में एनडीए सरकार के रिकॉर्ड को देखते हुए सैन्य कार्यवाही की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। वर्ष 2016 में उरी में हुये आतंकी हमलों के बाद, सरकार ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जबकि 2019 में हुये पुलवामा आतंकी हमले के बाद, बालाकोट स्ट्राइक की गई थी।

रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान-स्थित "रैजिस्ट्रेंस फ्रंट", जो प्रतिबंधित

पाकिस्तानी लश्कर-ए-तौयबा का शौडे-ग्रुप है, के चार आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 26 लोग मारे गये। इनमें से दो आतंकी स्थानीय बताये जा रहे हैं।

इस आतंकी हमले से चंद्ररोज पहले, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीर को जयपुर वन (ग्रीवा शिरा) बताया था, हालाँकि, पाकिस्तान सरकार

ने इस घटना में देश के लिप्त होने से इनकार किया है। लेकिन भारत सरकार का निश्चित तौर पर मानना है कि यह हमला लश्कर-ए-तौयबा द्वारा ही कराया गया है।

नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी की एक टीम, स्थानीय पुलिस की सहायता के लिये, पहलगाम पहुँच गई है तथा इस हमले में शामिल तीन लोगों के स्कैंच तैयार कर लिये गये हैं। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है, जब अमेरिकन उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस भारत यात्रा पर आये हुए हैं।

जहाँ अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को संबल और सहानुभूति प्रेषित की है, वहीं बहुत से पश्चिमी देशों के साथ ही, सऊदी अरब ने भारत को समर्थन एवं सहयोग देने की मंशा जाहिर की तथा पहलगाम हमले की निंदा की है। आगामी दिनों में, भारत पौ 5 देशों के प्रतिनिधियों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहलगाम के तीन आतंकवादियों के स्कैंच जारी

श्रीनगर, 23 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले में शामिल तीन संदिग्ध आतंकियों के स्कैंच सुरक्षा एजेंसियों ने बुधवार को जारी किए। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबु तल्हा बताए गए हैं।

इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि हमले का मास्टर माइंड लश्कर-ए तौयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो

■ जाँच के अनुसार पहलगाम हमले में 5 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से 2 स्थानीय थे।

पाकिस्तान में मौजूद है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इनमें से दो लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी थे।

जांचकर्ताओं का मानना है कि हमलावर सेना जैसी बर्दी में थे और उन्हें हमले से पहले इलाक़े की रेकी करने में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)